

CONTENTS

**Fifteenth Series, Vol. X, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 4, Thursday, July 29, 2010/ Sravana 7, 1932 (Saka)**

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
OBITUARY REFERENCES	1-2
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 61 to 80	8-69
Unstarred Question Nos. 691 to 920	70-422

PAPERS LAID ON THE TABLE 423-425

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT 426
10th to 13th Reports

STATEMENT BY MINISTER 427-428

Status of implementation of the recommendations contained in the First Report of Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Demands for Grants (2009-10) pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas

Shri Jitin Prasada

MOTION RE: SEVENTEENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 429

MATTERS UNDER RULE 377 430-437

- (i) Need to allocate funds for gauge conversion work on Bahraich-Nanpura-Rupaidiha railway section in North Eastern Railways

Shri Kamal Kishore 'Commando' 430

- (ii) Nee to set up a separate institutional authority to monitor the allocation and implementation of grants for the upliftment of SCs and Sts

Shri Rajaiah Siricilla 430A

- (iii) Need to introduce CNG based vehicles in the country, particularly in Hyderabad

Shri Ponnamp Prabhakar 431

- (iv) Need to set up Kendriya Vidyalayas in Bhadrachalam and Warrangal district of Andhra Pradesh

Shri P. Balram 432

- (v) Need to ensure adequate supply of fertilizers at affordable rates to the farmers of Zahirabad and Medak regions in Andhra Pradesh

Shri Suresh Kumar Shetkar 433

- (vi) Need to grant residency rights and identity cards to Hindu/Sikh nationals who have come from Pakistan on valid Visas
- Shri Pratap Singh Bajwa 434
- (vii) Need to shift Bagdad Asmara firing range in Karnataka to some other place
- Shri Suresh Angadi 435
- (viii) Need to promote Junior Engineers of Bhakra Beas Management Board to the post of Sub-Divisional Officer
- Shri Anurag Singh Thakur 436
- (ix) Need to increase wages of workers engaged in cooking mid-day meals in rural areas of the country, particularly in Jalgaon Parliamentary Constituency, Maharashtra
- Shri A.T. Nana Patil 437
- (x) Need to extend the Rajgir-Tilaiya rail section upto Koderma in East Central Railway Zone
- Dr. Bholu Singh 438
- (xi) Need to clear the backlog of pending cases in various courts
- Dr. Shafiqur Rahman Barq 438
- (xii) Need to provide security cover to the fishermen of Nagapattinam Parliamentary Constituency in Tamil Nadu who are being attacked by the Sri Lankan Navy
- Shri A.K.S. Vijayan 439

**STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF
PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO
THE STATE OF JHARKHAND** 440

Shri Ajay Maken 440
440

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 441

Member-wise Index to Unstarred Questions 442-445

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 446

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 447

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, July 29, 2010/ Sravana 7, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCES

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of two of our former colleagues, Shri Mohan Lal Jhikram and Shri Shiv Charan Gupta.

Shri Mohan Lal Jhikram was a Member of the Eighth, Ninth and Tenth Lok Sabhas from 1984 to 1996, representing the Mandla Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh. Earlier, Shri Jhikram was a Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 1980 to 1983. During this period, he held the position of the Deputy Minister for Education in the Government of Madhya Pradesh from 1983 to 1984.

Shri Jhikram was a Member of the Committee on Papers Laid on the Table during the Eighth Lok Sabha. He was a Member of the Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament and the Consultative Committee of the Ministry of Communications during the Tenth Lok Sabha.

An active social and political worker, Shri Jhikram served as the President of the District Cooperative Society, Mandla, Madhya Pradesh from 1983 to 1984 and President, Madhya Pradesh Tribal Cell from 1985 to 1991. He also served as the President, Forest Produce Committee, Jabalpur and the District Yojana Mandal, Mandla, Madhya Pradesh. He was the Vice-President of the All India Farmers' Committee from 1990 to 1991 and a Member of the Flood Control Board, Madhya Pradesh from 1980 to 1984.

An educationist by profession, Shri Jhikram was a recipient of the National Award for best teacher in 1963. Shri Jhikram worked relentlessly for rural uplift through the promotion of adult education and eradication of various social evils.

Shri Mohan Lal Jhikram passed away on 6th June, 2010 at Mandla, Madhya Pradesh at the age of 91.

Shri Shiv Charan Gupta was a Member of the Third Lok Sabha from 1962 to 1967 representing the Delhi Sadar Parliamentary Constituency of Delhi.

Earlier, Shri Gupta was a Member of the Delhi Legislative Assembly from 1952 to 1956. During this period, he held the position of Deputy Minister in the Delhi

Government from 1953 to 1954. Shri Gupta served as the Chairman, Standing Committee, Municipal Corporation of Delhi from 1958 to 1962.

Shri Gupta played a proactive role in the campaigns for the betterment of health facilities for the poor and downtrodden. He was also instrumental in setting up of an educational institution in Delhi.

Shri Shiv Charan Gupta passed away on 26th July, 2010 at the age of 88.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved families.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.05 hrs.

The Members then stood in silence for a short while

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज सुबह मुझे नियम 184 के तहत चर्चा कराने हेतु नोटिसेज मिले हैं जिसमें नेता, प्रतिपक्ष का भी नोटिस है। मैं उन्हें एग्जामिन कर रही हूँ।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : मैं वही कह रही हूँ कि मुझे नोटिस मिले हैं, आपका भी नोटिस मिला है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैडम, मुझे आपसे केवल एक ही बात कहनी है कि कल आपने एक रुलिंग देकर हमारे एडजर्नमेंट मोशन को खारिज कर दिया। आप पीठ पर हैं और हमारे लिए पीठ सर्वोच्च होती है। मैं आपकी रुलिंग के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं कर सकती और न करना चाहूंगी। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि हमें उस रुलिंग से दुख पहुंचा और निराशा हुई। आपने अंत में यह कहा कि यदि हम किसी और नियम के तहत नोटिस दें तो उसे कंसीडर किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने नियम 184 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया। लेकिन नियम 184 के नोटिस के साथ हम लोगों ने एक कवरींग लैटर भी दिया और प्रश्नकाल स्थगन का एक और निवेदन किया। एडजर्नमेंट मोशन न मानने के कारण से पिछले तीन दिनों से चर्चा नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज का प्रश्नकाल स्थगित करके नियम 184 का नोटिस ले लें, हम उसमें चर्चा आज प्रारम्भ कर दें जिससे सदन चल जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, हमने भी नोटिस दिया हुआ है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, आज नियम 184 के तहत चर्चा कराने के लिए और प्रश्नकाल के सस्पेंशन के लिए हमने भी नोटिस दिया है। कल हम लोग सरकार से गुहार लगाने आए थे और प्रणव बाबू जी से भी हमने बहुत गुहार लगाई तथा आपसे हमने बहुत गुहार लगाई। हम जब बाहर जाते हैं तो जनता हमसे कहती है कि आप क्या कर रहे हैं और यहां जब आते हैं तो सरकार भी दुतकारती है तथा कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। जिस तरह से कल एडजर्नमेंट मोशन का हमने नोटिस दिया था, उसे आपने खारिज कर दिया। हमारी रक्षा और सुरक्षा की कोई जगह है तो वह आपके यहां हैं। एक वर्ष हो गया, आपका प्रेम प्रणव बाबू की तरफ तो खूब झलकता है लेकिन हम लोगों की तरफ आपकी दया कभी नहीं होती। कल आपने फैंसला दे दिया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि रात भर पूरे अपोजीशन के लोग सो नहीं पाए हैं। हम लोग सोचते रहे

कि क्या करें? यानी अब अध्यक्ष जी से कैसे लड़ें? अध्यक्ष जी तो सर्वोच्च हैं, उनसे लड़ना तो मुश्किल है, उनसे कैसे लड़ा जाए? इसी बात पर हम लोग बहुत विचार मंथन करते रहे और किसी तरह से हम लोग नियम 184 लाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल आपके फ़ैसले से जनता को भी बहुत तकलीफ़ हुई है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अभी प्रश्नकाल सस्पेंड करिए। बाहर हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए मेरी फिर आपसे करबद्ध विनती है कि आप नियम 184 के तहत चर्चा कराने के लिए तो मान ही जाइए। आपने खुद कल कहा था। अब एडजर्नमेंट मोशन की धारा बिल्कुल बेकार ही हो गई है।... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): मैडम, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : मैंने कहा है, आपने नोटिस दिया है। आप बोल सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : यह तो कहीं रूल नहीं है कि आप मेरे बाद नहीं बोल सकते हैं। आप मेरे बाद बोल सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): मैडम, हमने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदया : उनको बोलने दीजिए। फिर आप भी बोल लेना। आपको भी बुलवाएंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : मैडम, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि हम किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। ... (व्यवधान) हम हर वक्त यह बात कहते रहते हैं कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं और कल इसी बात पर डेढ़ घंटा चर्चा हो गई। यही बात सभी सदस्यों ने कल कही और मालूम नहीं शरद यादव जी कैसे यह बात कह रहे हैं। 27 तारीख को श्री सुदीप बंदोपाध्याय और श्री राय ने दो नोटिसेज नियम 193 में दिये हैं। उन नोटिसेज के तहत चर्चा आप आज ही करवा सकते हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल लीजिए

... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : आप सरासर असत्य बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, हम शांत तरीके से सदन चलाना चाहते हैं। हम सदन में किसी प्रकार की अशांति नहीं चाहते हैं। आप जिस जगह बैठी हैं, वहाँ देख रही है कि सरकार कभी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि हमने अपनी पार्टी की तरफ नोटिस दिया है। जैसे हम अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए, यह बीच में खड़े हो गए।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको भी बुला रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें अपनी बात कहने का हक है, आप समय देंगी तो अच्छा है और अगर नहीं देंगी तो और तरीका अपनाएंगे, सीधी बात है। शरद यादव जी ने नोटिस दिया, हमने नोटिस दिया है। अब हम लोग एक राय के हो चुके हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है जब ऐसे समय पूरा विपक्ष एक राय का हो। अंदर से ये लोग भी बहुत चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।...(व्यवधान) आपके चिल्लाने से क्या हो जाएगा? मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर सबसे पहले नियम 184 के अधीन चर्चा कराएं। हम इसके लिए लगातार परसों से मांग कर रहे हैं। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता तो आज सदन का यह हाल नहीं होता। अगर सदन नहीं चल पा रहा है तो सरकार जिम्मेदार है। महोदया, आप सरकार की जिम्मेदारी मत लीजिए। आप क्यों सरकार की जिम्मेदारी ले रही हैं? आप तो कुर्सी पर बैठी हैं। स्पीकर हमेशा विपक्ष को संरक्षण देते हैं। ये बात नहीं मानेंगे और हर तरह से मनमानी करेंगे। हम चाहते हैं कि नियम 184 के अधीन चर्चा करायी जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही चले।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, हमने भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदया : आपका नोटिस नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : हर काम नियम और कानून से होता है। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। कल से चर्चा हो रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्न काल शुरू होने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : लोकसभा नियम और कानून से चलती है। हमने कल भी नोटिस दिया था।...(व्यवधान) नियम और कानून तो देश की जनभावना के लिए बनते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नियम 184 की एक प्रक्रिया है, उसे एग्जामिन कर लेने दीजिए। अगर हम इसे एडमिट कर लेते हैं तो यह बीएसी के सामने जाएगा। आप उतना समय दीजिए और बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : देश की गरीब जनता की पीड़ा से बड़ा कानून नहीं है। हमारी मांग है कि सारा कामकाज बंद करके पहले नियम 184 के अधीन चर्चा कराई जाए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब प्रश्न काल चलने दीजिए। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, इस सदन में सबसे पहले महंगाई विषय को लेकर चर्चा होगी। अगर हमारा काम रोको प्रस्ताव खारिज हो गया है तो नियम 184 लीजिए क्योंकि विषय तो वही है, लेकिन आप कह रही हैं कि अभी महंगाई के मुद्दे को छोड़कर प्रश्न काल चलने दिया जाए।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हम इसे नियम 193 के अधीन ले चुके हैं।...(व्यवधान) 27 तारीख को दो नोटिस नियम 193 के अधीन आ चुके हैं क्योंकि वे नोटिस पहले नियम 193 में आ चुके हैं इसलिए उसमें चर्चा हो जानी चाहिए।...(व्यवधान) हम चर्चा की बात कह रहे हैं और ये रूल की बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल शुरू करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महंगाई की चर्चा के सिवाय कोई दूसरा काम इस सदन में नहीं होगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल तो शुरू करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होगी। हमने नियम बदल दिया है। हमने आपकी रूलिंग के बाद स्थगन प्रस्ताव छोड़ दिया। आप नियम 184 के अधीन चर्चा कराइए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप भी जानती हैं कि मुझे इसे देखकर निर्णय लेना है। अगर उसे एडमिट किया जाएगा तो वह बीएसी के सामने जाएगा। आप सब कुछ जानती हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : देश का सबसे बड़ा प्रश्न महंगाई है।...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हम चर्चा की बात कहते हैं ये रूल की बात कहते हैं।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Q. No. 61.

... (Interruptions)

11.14 hrs.

At this stage, Shri Mithilesh Kumar, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 noon.

11.15 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Madam Speaker in the Chair)

... (Interruptions)

12.0¼ hrs.

At this stage, Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

... (व्यवधान)

12.0½ hrs.

At this stage, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

... (व्यवधान)

12.0¾ hrs.**PAPERS LAID ON THE TABLE**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Competition Appellate Tribunal (Recruitment, salaries and other terms and conditions of service of officers and other employees) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 290(E) in Gazette of India dated the 8th April, 2010, under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 2639/15/10)

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Handloom Development Corporation Limited and the Ministry of Textiles for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2640/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI JITIN PRASADA): Madam, I beg to lay on the Table:--

- (1) A copy of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 452(E) in Gazette of India dated the 28th May, 2010, under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 2641/15/10)

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

- (i) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determining Capacity of Petroleum, Petroleum Products and Natural Gas Pipeline) Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 476(E) in Gazette of India dated 7th June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2642/15/10)

- (ii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and other Charges) Amendment Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 477(E) in Gazette of India dated 7th June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2643/15/10)

- (iii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 478(E) in Gazette of India dated 7th June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2644/15/10)

- (iv) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Network Tariff for City or Local Natural Gas Distribution Networks and Compression Charge for CNG) Amendment Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 479(E) in Gazette of India dated 7th June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2645/15/10)

- (v) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 480(E) in Gazette of India dated 7th June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2646/15/10)

- (vi) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Regulations, 2010 published in Notification No. G.S.R. 481(E) in Gazette of India dated 7th June, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2647/15/10)

12.02 hrs.

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

10th to 13th Reports

SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN (INDORE): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:--

- (1) Tenth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the First Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).
- (2) Eleventh Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Second Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).
- (3) Twelfth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Third Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Ministry of Rural Development (Department of Drinking Water Supply).
- (4) Thirteenth Report on action taken by the Government on the recommendations contained in the Fourth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) of the Ministry of Panchayati Raj.

... (*Interruptions*)

12.02½ hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the First Report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Petroleum and Natural Gas *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI JITIN PRASADA): Madam, I beg to lay the Statement on the status of implementation of recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas (15th Lok Sabha) in pursuance of directions of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin- part II dated September 01, 2004.

The First Report of the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas (15th Lok Sabha) was presented to the Lok Sabha on 21.12.2009. The Report relates to the examination of Demands for Grants of Ministry of Petroleum & Natural Gas for the year 2009-10. Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report of the Committee had been sent to the Standing Committee on Petroleum & Natural Gas on 16.3.2010.

There are 29 recommendations made by the Committee in the said Report where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to issues like full utilization of Budget, setting up of Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, availability of rigs for exploratory drilling, realistic targets for exploratory works, timely commissioning of Paradip refinery, achieving crude oil production targets, strengthening of Directorate General of Hydrocarbon, development of alternate sources of fuel, according infrastructure status to hydrocarbon industry, taking steps to attract adequate response from domestic and foreign companies under New Exploration Licencing Policy, increased allocation for

* Laid on the Table of the House and also placed in Library, See No. LT 2648/15/10

Research & Development activities, taking up projects in areas like development of shale gas and gas hydrate resources, conversion of coal to liquid, creation of Price Stabilization Fund, compliance of environmental norms by Refineries, Bio-fuels, year-wise action plan for CNG/PNG network, Rajiv Gandhi Gramin LPG Vitrak Yojana, curbing of adulteration and automation of Retail Outlets, setting up of Strategic Storage facilities, restructuring of Biecco Lawrie Limited, etc.

Present status of implementation of various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to the Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House by reading out all the contents of this Annexure. This may please be considered as read.

12.03 hrs.

**MOTION RE: SEVENTEENTH REPORT OF
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to move the following:--

“That this House do agree with the Seventeenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 28th July, 2010.”

MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House do agree with the Seventeenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 28th July, 2010.”

The motion was adopted.

12.03¼ hrs.**MATTERS UNDER RULE 377***

MADAM SPEAKER: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House immediately, as per practice.

(i) Need to allocate funds for gauge conversion work on Bahraich-Nanpura – Rupaidiha railway section in North Eastern Railway

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): मेरे संसदीय क्षेत्र का जनपद बहराइच (उ०प्र०) नेपाल का सीमावर्ती इलाका है। यहां बहराइच से नानपारा नेपालगंज रोड. तक मीटर गेज रेल मार्ग है। गोंडा-बहराइच-नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड. के रास्ते काफी संख्या में दोनों देशों के लोगों का आवागमन रहता है। रूपईडीहा बार्डर वाणिज्यिक सामानों का आने जाने का दोनों देशों का प्रमुख केन्द्र है। मीटर गेज होने के कारण यहां से रेल मार्ग से दुलाई नहीं हो पाती है। जनहित में बहराइच नानपारा नेपालगंज रोड. रेल मार्ग का आमान परिवर्तन किया जाना अति आवश्यक है। इस रेल मार्ग के आमान परिवर्तन से रूपईडीहा से सीधे तौर पर देश के अन्य भागों का सीधा संपर्क हो जाएगा, जिससे यात्रियों से तथा माल भाड़ा से रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होगी तथा भारत नेपाल दोनों देशों के मध्य और मजबूत संबंध कायम होगा जिसकी आज के परिदृश्य में बहुत ही जरूरत है। साथ ही बहराइच जैसे गरीब व पिछड़ इलाके का विकास होगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत बहराइच-नानपारा नेपालगंज रेल मार्ग का आमान परिवर्तन वर्ष 2011-12 में करने की स्वीकृति प्रदान करने व धन आबंटित करने की कृपा करें।

* Treated as laid on the Table

(ii) Need to set up a separate institutional authority to monitor the allocation and implementation of grants for the upliftment of SCs and STs

SHRI RAJIAH SIRICILLA (WARANGAL): I would like to draw the kind attention of the august House towards allocation and expenditure made under Special Component Plan (SCP) and Tribal sub plan (TSP). As per the guidelines 16.2% and 8.0% of grants are to be allocated for SCs and STs respectively. There are certain Ministries/Departments which are neither in a position to allocate the grants nor incur expenditure. Even if they allocate, they do not spend the grants for the welfare of SCs/STs. At the end of financial year they divert these funds to some other programmes. It is worth to mention here, that in certain Ministries/Departments, the amounts are mathematically/arithmetically divided into 16.2% and 8.0% and shown spent against the SCs and STs respectively.

Hence, I request the Government that there is a need to formulate a plan to increase the allocation in addition to the allocation of 16.2% and 8.0% towards SCs and STs, so as to enable to bring down the gap. Therefore, I strongly believe that, there must be a separate institutional mechanism or a separate authority to monitor the allocation and effective implementation of SCP/TSP duly turning the allocations to implementable schemes.

(iii) Need to introduce CNG based vehicles in the country, particularly in Hyderabad

SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the need to introduce CNG in Hyderabad and other cities to reduce the pollution which affects the health of the people in our country.

CNG is the only alternative to stop alarming pollution levels in Metro cities like Hyderabad. With increase in petrol prices acceptance level of alternate fuel vehicles among Indian is growing. CNG wave seems to spread fast across India and there is a dire need to introduce CNG in other cities like Hyderabad. Currently, the availability of CNG is confined to selected centres in Western and northern India only. The LPG dispensing stations have been concentrated on specific cities, and cities of South India especially cities of Andhra Pradesh remains almost negligible. I would like to mention some successful initiatives like conversion of diesel fueled Public transport to CNG fueled transport in Delhi, switching of Vikrams (tuk-tuks) from using diesel to electricity as fuel in Kathmandu valley, shifting from leaded to unleaded gasoline in many countries to reduce the pollution level.

I, therefore, request the Minister of Petroleum & Natural Gas, to introduce CNG based vehicles in Andhra Pradesh and also in other cities across the country in the current year itself with sufficient budgetary allocations.

(iv) Need to set up Kendriya Vidyalayas, in Bhadrachalam and Warrangal districts of Andhra Pradesh

SHRI P. BALRAM (MAHABUBABAD): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the need to set up at least two Kendriya Vidyalayas, one in Bhadrachalam area and another in Warangal district i.e. in my Mahabudabad Constituency, in Andhra Pradesh.

Nearly 30 schools are catering to the needs of the students in Andhra Pradesh. Students are being benefited very much from these schools especially the poor ones like tribals. Most of the people who are living in and around the areas of Bhadrachalam, Illendu, and in other areas in Mahabubabad Constituency belongs to SCs/STs/BCs and other minority sections and many people are poor and they are striving for their livelihood with their meagre incomes. Most of the students are unable to afford the cost of education in private institutions due to utter poverty and lack of knowledge. There is necessity to cater to the needs of the students who are mostly from weaker sections and the tribals. If the Government sets up adequate Kendriya Vidyalayas in my Mahabubabad Constituency, the students particularly hailing from tribal belts will be mostly benefited and definitely it will increase the knowledge levels in all parts of our country with a uniform procedure.

I, therefore, request the Hon'ble Minister of Human Resource Development, to intervene in the matter and ensure that at least two Kendriya Vidyalayas one in Bhadrachalam and another in Warangal district may be set up in the remaining XI Plan period.

(v) Need to ensure adequate supply of fertilizers at affordable rates to the farmers of Zahirabad and Medak regions in Andhra Pradesh

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHEERABAD): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the problems being faced by the farmers in getting fertilizers in time and at an affordable price not only in Andhra Pradesh but all over the country especially in Telangana areas like Zaheerabad and Medak.

Many farmers are facing lot of problems in getting the fertilizers for various crops purposes in the kharif and rabi seasons at the minimum rates fixed by the Government. Sometimes, there is no stock or the farmers have to stand in queue for many hours due to lack of adequate fertilizers or they have to spend more amount in the black market. Some people and companies are creating shortage of such supply of fertilizes in the market. Many farmers were duped in recent years due to lack of awareness in the supply of fertilizers. There is no proper system to monitor the sale of fertilizers in the market at MRP rates particularly in the remote areas like Zaheerabad, Medak and other Telangana regions in Andhra Pradesh. This is really a concerned issue of the farmers and the overall development of our country. Now, this is the right time for the Government to ensure proper supply of fertilizers to sow the seeds.

I, therefore, request the concerned Hon'ble Minister, to kindly intervene in the matter to ensure that farmers get their fertilizers in time and at MRP rates in all seasons by strictly monitoring the market so that the interests of the farmers could be protected to get the genuine returns for their hard work in improving our economy and growth.

(vi) Need to grant residency rights and identity cards to Hindu/Sikh nationals who have come from Pakistan on valid Visas

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): There are thousands of Hindu/Sikh families who came to India from Pakistan on a valid Visa, but do not want to go back for various reasons. One of their chief fears is the prevailing law and order situation is very bad in Pakistan, besides their poor economic conditions. There are some nationals who stayed back in Pakistan at the time of partition for various compulsions, but now they want to come back to their motherland for the rest of their lives. In some cases, it has even been reported that they have torn their passports into pieces so that they would not be forced to go back to their homes in Pakistan.

Recently, the Ministry of Home Affairs has asked the State Governments/UT Administration to consider the cases for extension of long-term visa of certain categories of Pakistani nationals, and also granted exemption to such Pak nationals from the provisions of Rule 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920.

However, it is the desire of these nationals that instead of extension of long-term of visa, they should be given asylum in India so that they can get residency rights and identity cards to enable them to have access to various welfare schemes.

I, therefore, request the Hon'ble Minister to kindly take a sympathetic view on this matter and issue necessary directions in this regard.

(vii) Need to shift Bagdad Asmara firing range in Karnataka to some other place

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): An area of 7469.11 acres of agricultural land situated in various villages of Belgaum taluka have been reserved for Bagdad Asmara Firing Range upto year 2020. These lands are of private owners. It has become very difficult for them to go to their fields and take up agricultural and non-agricultural activities in their own lands. Moreover, the students, farmers and the general public are using the roads passing through these lands which have been reserved for firing range.

For the sake and safety of life of the villagers, farmers and students the present firing range is to be shifted. These private agricultural land owners have not been paid any compensation so far causing financial constraints to them and they are being restricted to use their agricultural lands. Further, the reserved firing range is situated in the middle of the extended fast developing Belgaum city. Thus the already reserved firing range in the village limits of Ramdurg and Marihal of Belgaum Taluk can be used by the Defence Department. In fact, the Army has about 28000 acres of land with them, which they are not using since independence.

I urge upon the Union Government to consider shifting the reserved firing range, as per public demand and their interest.

(viii) Need to promote Junior Engineers of Bhakra Beas Management Board to the post of Sub-Divisional Officer

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए जूनियर इंजीनियर्स को एस.डी.ओ के रूप में पदोन्नत नहीं किए जाने से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बी.बी.एम.बी. में स्वयं बोर्ड द्वारा नियुक्त जूनियर इंजीनियर्स को सेवा करते हुए 20-20 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें एस.डी.ओ के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। विभिन्न विभागों से बी.बी.एम.बी में प्रतिनियुक्ति पर आए कनिष्ठ अभियंताओं को तो एस.डी.ओ के रूप में एडहॉक प्रमोशन दी जा रही है, लेकिन स्वयं बोर्ड द्वारा नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। इससे उनमें असंतोष व्याप्त है। बी.बी.एम.बी द्वारा स्वयं नियुक्त किए गए कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम 1984 में बनाए गए, लेकिन क्लास-टू कैडर को पदोन्नत करने के नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि क्लास-टू कैडर की पदोन्नति के नियम बनाने हेतु तत्काल निर्देश दिए जायें और जब तक पदोन्नति संबंधी रैगुलेशन्स नहीं बनते हैं, तब तक योग्य कनिष्ठ अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से एस.डी.ओ. के रूप में पदोन्नत किया जाये।

(ix) Need to increase wages of workers in cooking mid-day meals in rural areas of the country, particularly, in Jalgaon Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने संबंधी सरकार की वचनबद्धता और विशेषकर ग्रामीण अंचलों में बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का अद्वितीय उदाहरण है, किंतु इस योजना में कुछ खामियां हैं। इस योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले आहार में जहां पौष्टिक तत्वों की कमी की शिकायतें आई हैं, वहीं आहार की गुणवत्ता के साथ समझौता करने की आवाजें भी उठती रहीं हैं। मैं इन्हीं कमियों के मुख्य बिन्दु के बारे में बात करना चाहता हूं। हमारे देश में छोटे एवं बड़े शहर हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान उन छोटे गांवों की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां बच्चे केवल भोजन के लिए ही स्कूल आते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव में बहुत सारे छोटे-छोटे गांव हैं, जिसमें औसतन 70 से 80 बच्चे एक स्कूल में आते हैं। परन्तु स्कूल में भोजन बनाने और बांटने के लिए जिसे नियुक्त किया जाता है, उसका मानदेय अत्यंत थोड़ा होने के कारण भोजन की गुणवत्ता व नियमितता दोनों बेकार हो गई हैं। बच्चों को खाना नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो खाने लायक नहीं रहता है। क्योंकि जो भी खाना बनाता है, उसको उसका मेहनताना कम मिलने के कारण यह स्थिति आ गई है। इस भोजन तथा योजना का कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि कोई महिला खेतों में भी मजदूरी के लिए जाती है तो उसका कई गुना मजदूरी मिलती है। इसके चलते कोई भी महिला भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमारी यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना अंत के कगार पर है।

अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसका मेहनताना बढ़ाकर 150 से 200 रुपये प्रतिदिन करना चाहिए जिससे हमारा शिक्षित भारत का सपना है, वह पूरा हो सके।

(x) Need to extend the Rajgir-Tilaiya rail section upto Koderma in East Central Railway Zone

डॉ. भोला सिंह (नवादा): मध्य-पूर्व रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत राजगी-तिलैया रेलखंड का जो प्रचालन हुआ है, उसका विस्तार तिलैया से कोडरमा तक करने की आवश्यकता है। रांची से कोडरमा रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है। तिलैया के कोडरमा रेल लाइन से जुड़ जाने से रांची एवं दक्षिण भारत की यात्रा सुलभ एवं सुगम हो जायेगी। ज्ञातव्य हो कि 2002-03 में तिलैया-कोडरमा रेल खंड के निर्माण की योजना स्वीकृत भी हुई थी। इसका शिलान्यास तत्कालीन रेल मंत्री ने तिलैया में किया था। तिलैया के कोडरमा से जुड़ जाने के कारण तिलैया एक जंक्शन का स्वरूप ग्रहण कर सकेगा एवं पूरे भारत में रेलवे की एक नई लाइन का शुभारंभ होगा। मैं इस ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(xi) Need to clear the backlog of pending cases in various courts

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): आपका ध्यान मैं सुप्रीम कोर्ट सहित देश की सभी अदालतों में लंबित पड़े लगभग 2,72,76,000 मुकदमों की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ जजों के बयान के मुताबिक भी इन मुकदमों के निपटाने में सैंकड़ों साल लग जायेंगे, जो कि बेहद चिंता का विषय है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देशभर की अदालतों में लंबित पड़े दो करोड़ बहत्तर लाख छियत्तर हजार मुकदमों का किसी नई प्रणाली से निपटारा करवायें।

(xii) Need to provide security cover to the fishermen of Nagapattinam Parliamentary Constituency in Tamil Nadu who are being attacked by the Sri Lankan Navy

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I would like to bring the attention of the Minister of External affairs to the continued atrocities being committed by Sri Lankan Navy on the India Fishermen. Recently, four fishermen from Vedaranyam Area, which falls in my Constituency, Nagapattinam, Tamil Nadu were brutally attacked by Sri Lankan Navy during fishing in the sea near the coast of Kodiakarai. One of the fishermen, lost his life in the sea. Frequent occurrence of such attacks by Sri Lankan navy on the fishermen of my Nagapattinam Constituency has caused nightmare in the minds of the fishermen who venture into the sea for fishing.

I hope that the Ministry of External Affairs would take up this issue strongly with Sri Lanka and would find a permanent solution to this problem. I would also request the Minister of Home Affairs to strengthen the patrolling by Coast Guard. It should be the duty of the Coast Guard and Indian Navy to protect each and every Indian fishermen. Unfortunately the fishermen are left to the mercy of Sri Lanka Navy whenever they venture into the sea. Even though we are extending assistance in many ways, the attitude of Sri Lankan Navy towards the Indian fishermen is a cause of concern in the State.

I hope that the Union Government would initiate immediate measures to protect our fishermen.

12.03½ hrs.**STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF PROCLAMATION BY
PRESIDENT IN RELATION TO THE STATE
OF JHARKHAND – Contd.**

MADAM SPEAKER: Item No. 11, further discussion on the Statutory Resolution.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): Madam Speaker, a copy of the Proclamation, as stipulated under the Constitution, along with consequential Order is also placed on the Table of the House. In keeping with the convention, a copy of the Governor's report recommending issuance of the Proclamation is also placed on the Table of the House.

Yesterday, I have already moved the Resolution. Now, I would request that the Proclamation issued on the 1st June, 2010 under article 356 (1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand be approved by this august House.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That this House approves the Proclamation issued by the President on the 1st June, 2010 under article 356 (1) of the Constitution in relation to the State of Jharkhand.”

The motion was adopted.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 30th of July, 2010, at 11.00 a.m.

12.04 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, July 30, 2010/Sravana 8, 1932 (Saka).*

